

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
5/3/24	<u>आदेश (6/24)</u> आवेदक सुरदेव पिता स्न० सरगु पासवान साकिन- लुकुईया घाना- बगौदर जिला- गिरि- डीह तथा अन्य के आवेदन पर अंचल प्रम० बगौदर के जौच प्रतिवेदन के आलोक में मौजा- लुकुईया, घाना- बगौदर जिला- गिरिडीह स्थित भूमि, जिसका खाता न० 27 प्लॉट न० 110 रकबा- 81 बी० गैरहदी उ० निज प० पदुम पासवान पू० रास्ता प० निज प्रम० पर, पर प० प्र० सं० की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा प्रवृत्त किता तथा अभय पक्ष को उक्त भूमि पर जाने अबका कोई कार्य करने से प्रतिबंधित किता। उक्त पक्ष से कारण पृच्छा भी की गई। उभय पक्ष के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किता गया। प्रथम पक्ष का कहना है कि तकरारी भूमि उनके पूर्वज ओपन दुसाप्प को बैदु दुसाप्प को बन्दोबस्ती से हासिल है तथा उक्त भूमि की जमाबन्दी अंचल बगौदर के पेजी-II के पृष्ठ सं० 11 Volume No. 02 पर कायम है। प्रथम पक्ष का यह भी कहना है कि उक्त भूमि का लगान रसीद लगाना निर्गत होते आ रहा है। प्रथम पक्ष का आगे कहना है कि उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किए जाने के कारण यह विवाद उत्पन्न हुआ है। प्रथम पक्ष अपने दावे के समर्थन में ऑफलाइन पेजी-II की दाय्या प्रति, ऑफलाइन लगान रसीद की दाय्या प्रति प्रस्तुत करते हैं। वहीं वुसयी और द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रसंगत भूमि उनके पूर्वज कुप्पन महलौ वगैरह को बन्दोबस्ती से हासिल है। द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि तकरारी भूमि की जमाबन्दी कायम है तथा सरकारी लगान रसीद निर्गत होते आ रहा है। द्वितीय पक्ष आगे बताते हैं कि उक्त भूमि को लेकट्ट कुप्पन महलौ वगैरह बनाम ओपन महलौ पासवान के नाम से एक राइटरल सुर 199/2000 मुंसिफ कोर्ट गिरिडीह	(1/2)

में चला वा जिसमें Decree बुधन गहने के पक्ष में दिया गया था। द्वितीय पक्ष अपने दावे के सम्मान में एक online रजिस्ट्रार, न्यायनिर्णय की क्षमता, एक पुलह नामा तथा एक पंचायत नामा प्रस्तुत करते हैं।

उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत कागजातों के अध्ययन करने, उभय पक्ष के विद्वान अधिकारता के दलीलों को सुनने तथा अंशल अधिकारी वगैरह के औचक प्रतिवेदन का अवलोकन करने के उपरान्त मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि विवादिन जमीन को लेकर उभय पक्ष में स्वत्व संबंधी विवाद है। द.प्र.सं. की धारा 144 के तहत स्वत्व संबंधी निर्णय नहीं हो सकता है। साथ ही स्वत्व संबंधी विवाद के निपटारे के लिए वर्तमान दोनों पक्षकार के पूर्वज पूर्व में ही सशम न्यायालय चले गए थे तथा उक्त दोनों पक्षकार के पूर्वजों के द्वारा दिए गए पुलहनामा के आधार पर माननीय न्यायालय ने अपना न्यायनिर्णय दिया है। अतः प्रस्तुत वाद में कोई अंतिम आदेश पारित करना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को चाहिए कि उक्त न्यायनिर्णय का सम्मान सुनिश्चित करेंगे।

द.प्र.सं. की धारा 144(4) के तहत वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित्र एवं संशोधित

अनुमंडल पदा०
वगैरह सचिव

अनुमंडल पदा०
वगैरह सचिव

C.C-509464
20/11/24
20/11/24

C.C-509464
20/11/24
20/11/24